

पर सियासत कम होने की वजाय बढ़ना लाजिमी है। राफेल डील में मोदी सरकार भले ही अपनी पाक साफ छवि के लाख दावे करे और स्पष्टीकरण दे। भले ही वो जो कह रही हो वो सच भी हो, बावजूद इस मामले ने उसका सिरदर्द तो बढ़ा ही रखा है।

नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कुण्डली में जिस तीसरे ग्रह ने हलचल और अव्यवस्था फैला रखी है, उस ग्रह का नाम राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी जिसे भाजपा व उसके सहयोगी संगठन 'पप्पू' कहकर चिढ़ाते थे। आज उस पप्पू का आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि वो संसद में खड़ होकर कह सकता है कि, 'आपके लिए मैं भले ही पप्पू हूँ, आपके दिल में मेरे लिए नफरत हो सकती है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।' खुद पर तंज कसने और हंसने के लिये हिम्मत की जरूरत होती है।

वक्त के थपेड़ों ने राहुल गांधी में वो हिम्मत पैदा कर दी है। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री को ललकारते हुए 'चौकीदार चोर है' और 'नाकाबिल ईसान' तक कहने में झिझकते नहीं हैं। राहुल कहते हैं कि 'वे साबित करेंगे कि देश का चौकीदार चोर है।'

पिछले एक साल से कांग्रेस की कमान संभाल रहे राहुल अपनी छवि सुधारने के लिये कैलाश मानसरोवर यात्रा से लेकर जनेऊ धारी फोटो जारी करने के तमाम प्रपंच रच रहे हैं। अपनी व पार्टी को मुस्लिम परस्त की छवि को तोड़कर वो साफ्ट हिंदुत्व की छवि गढ़ने में कामयाब होते दिखाई देते हैं। गुजरात व कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के पसीने छुड़ाने के बाद हिंदी पट्टी के तीन राज्यों की जीत ने राहुल का राजनीतिक कद और लोकप्रियता दोनों को बढ़ाया है।

अब मोडिया भी उन्हें तवज्जो देने लगा है। आज राहुल गांधी एक नये ब्रांड के तौर पर उभरते दिखाई दे रहे हैं। हां, बीच-बीच में उनकी राजनीति, विचार, बांडी लैंग्वेज और कार्यशैली बेपटरी हो जाती है। जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंचती है। फिलवक्त राहुल नरेंद्र मोदी का विकल्प तो नहीं बन पाये हैं, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर मोदी के सबसे मुख्य राजनीतिक विरोधी बनकर जरूर उभरे हैं। मोदी को टकरा देने के लिये अभी उन्हें जन्तल से ज्यादा जुड़ाव, स्वीकार्यता हासिल करने के अलावा लगातार प्रदर्शन की जरूरत है।

लब्धोलुबाव यह है कि राम मंदिर, राफेल और राहुल गांधी मोदी की राजनीतिक कुण्डली में किसी अनिष्ट ग्रह की भांति सत्ता के घर में एक साथ बैठ गये हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्हें देश की जनता के साथ अपनी पार्टी और अपने लोगों को भी जवाब देना है। राफेल डील को कांग्रेस ने झगड़े की बजाय रगड़ बनाने का पूरा मन और तैयारी कर ली है। वहीं तेजी से उभरते ब्रांड राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री को आंख में आंख डालकर बात करने और बहस करने की खुली चुनौती कदम-कदम पर दे रहे हैं। मोदी को 2019 में सत्ता हासिल करने के लिये राम मंदिर, राफेल और राहुल गांधी रूपी राजनीतिक ग्रहों को शान्त करने का उपाय करना होगा। अगर इनमें से एक भी यह शक्तिशाली बनकर उभर आया तो वो मोदी के दोबारा राजतिलक के अरमानों पर पानी फेरने का काम कर सकता है।

सपा-बसपा से गठबंधन की उम्मीद खत्म होने के बाद कांग्रेस की नई रणनीति

गौरतलब हो, बसपा-सपा से गठबंधन की उम्मीद खत्म होने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैलियों के कार्यक्रम को नए सिरे से बनाया है। राहुल की प्रदेश में प्रस्तावित एक दर्जन रैलियों की शुरुआत लखनऊ से होगी। जल्द ही रैली की तारीख फाइनल कर ली जाएगी।



लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भटकाव जारी है। हालात यह हैं कि बसपा-सपा से दुल्कारे जाने के बाद भी कांग्रेस यह तय नहीं कर पाई है कि वह इन दोनों दलों के खिलाफ क्या रूख अख्तियार करें। यह स्थिति तब है जबकि बसपा और सपा नेता लगातार कांग्रेस पर हमलवार हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव जीतने से पहले ही सरकार कैसे बनेगी, इस पर ज्यादा मंथन कर रही है। कांग्रेस आलाकमान का यह रवैया कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा का भाव पैदा कर रहा है। बात आगे बढ़ाई जाए तो सम्पत्ता इसी मोर्चे तक सीमित नहीं है।

एक ओर जहाँ अन्य दल चुनाव के लिए बिसात बिछा रहे हैं, वहीं कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसमें उलझी हुई है। ऐन चुनाव से पहले पिछड़ों को लुभाने के लिए उसके द्वारा पिछड़ा वर्ग विभाग संगठन में विस्तार के साथ बदलाव भी किया जा रहा है। दावा यह है कि एक सप्ताह के भीतर विभाग के प्रदेश संयोजक की नियुक्ति के साथ कमेटी गठित कर ली जाएगी। जिला व ब्लाक इकाइयों के गठन की औपचारिकता 31 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश के एक लाख से अधिक गांवों में कमेटीय गतिज होंगी और प्रधान नामित किया जाएगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों द्वारा पिछड़ा वर्ग विभाग संगठन के माध्यम से सैनी, निषाद, कुर्मा कश्यप, कुशवाहा व लोधी जैसे जातियों को जोड़ने पर फोकस किए जाने की बात कही जा रही है।

पिछड़ों को लुभाने के लिये ही कांग्रेस पिछड़ा वर्ग समाज की महारैली मार्च के प्रथम सप्ताह में कराई जा रही है। महारैली से पहले जिला स्तर पर भी सम्मेलन कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियां कामयाब बनने में पिछड़ा वर्ग विभाग अहम भूमिका निभाए, इसके लिये जिला व ब्लाक इकाइयों के कामकाज की नियमित समीक्षा होगी। पिछड़ा वर्ग के वोटों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने नए सिरे से तैयारी शुरू की है। योजना है कि प्रदेश के सभी गांवों में पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधि तैनात किया जाएगा। उसे 'ग्राम प्रधान' नाम दिया जाएगा। एक महीने तक गांवों में पिछड़ों के बीच काम करने के बाद मार्च में फीडबैक के लिए सम्मेलन किया जाएगा। सपा-बसपा से गठबंधन के रास्ते बंद होते ही कांग्रेस पूरी ताकत से चुनावी तैयारी में जुट गई है। उसके द्वारा सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव को तैयारी है। ग्रामों में भी पिछड़ा वर्ग विभाग की कमेटी गठित करके प्रधान तैनात किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद से परत पड़े संगठन की सक्रियता लोकसभा चुनाव की आहत होते ही बढ़ी है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने के अभियान की निगरानी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अनिल सैनी संभाले हुए हैं। सैनी का दावा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के चुनाव नतीजों से सिद्ध हुआ पिछड़ा वर्ग तेजी से कांग्रेस की ओर लौट रहा है।

गौरतलब हो, बसपा-सपा से गठबंधन की उम्मीद खत्म होने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैलियों के कार्यक्रम को नए सिरे से बनाया है। राहुल की प्रदेश में प्रस्तावित एक दर्जन रैलियों की शुरुआत लखनऊ से होगी। जल्द ही रैली की तारीख फाइनल कर ली जाएगी।

यूपी कांग्रेस के लिये यॉह नहीं महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने यहां से देश को भारत और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के रूप में तीन-तीन प्रधानमंत्री दिए थे। यूपी की फूलपुर संसदीय सीट से 1952, 1957 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा चुनाव जीता था। नेहरू का 1964 में अपनी मृत्यु तक इस सीट पर कब्जा रहा। 1967 में उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित इस सीट पर काबिज रहीं। वहीं रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी सांसद बने थे। बाद में उनकी बहू और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने 2004 में यह सीट जीती। 2009 और वर्तमान में 2014 के चुनावों के बाद भी यह सीट उन्हीं के पास है। अमेठी सीट भी नेहरू-गांधी परिवार के पास है।

1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को यूपी से भारी बहुमत मिला था। उस वक्त 85 सीटों (तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था) पर लड़ने वाली देश की इस सबसे पुरानी पार्टी को 83 सीटें मिली थीं। तब कांग्रेस को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वाले इस राज्य में 51.03 फीसद वोट मिले थे। 1984 के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस का जनाधार गिरा है। 2014 के लोकसभा चुनावों में इसका वोट 07 प्रतिशत पर सिमट कर रह गया था। सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सोनिया और राहुल की ही लोकसभा सीट बचा पाई थी। प्रदेश मंस सपा-बसपा की ताकत बढ़ने के बाद पिछले तीन दशकों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत थी। लेकिन राम मनोहर लोहिया आंदोलन, मंडल आयोग और भाजपा की हिंदुत्व नीति ने राज्य में इस पार्टी का जनाधार खत्म कर दिया। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को उत्तर प्रदेश में खोई हुई साख वापस लौटाने की है तो दूसरी तरफ कई जिलों में कोई कमेटी नहीं होने से पार्टी तंत्र खस्ताहाल है। मतदाताओं-कार्यकर्ताओं पर समान रूप से पार्टी की पकड़ ढीली है।

वैसे कुछ जानकार कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने को उसकी आगे की सेहत में सुधार के लिए अच्छा बता रहे हैं। ऐसे लोगों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो वह करीब दो दर्जन सीटों पर सीधे जीत दर्ज करने का दाखल रखती है। इसके वजह 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। तब कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अकेले दम पर 21 सीटें तो सपा ने 23 और बसपा ने 20 सीटें हासिल की थीं, जबकि बीजेपी को 10 सीटें मिली थीं, लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों में मोदी लहर ने बीजेपी को 71 के जादुई आंकड़े तक उठकर ला खड़ा किया। बसपा एक सीट न जीत सकी, वहीं समाजवादी पार्टी महज 5 और कांग्रेस दो सीटों पर सिमट गई। आंकड़े बताते हैं कि 2014 में मोदी लहर में भी कांग्रेस ने प्रदेश की दो दर्जन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में सम्मानजनक स्थित हासिल की थी। इसमें भी करीब 6 सीटों पर पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को तगड़ी चुनौती दी, हालांकि जीत उसे नसीब न हो सकी। अब तीन राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई संजीवनी तो मिली है, लेकिन 2017 की यादें भी उन्हें डराती रहती हैं। परंतु फिर उसमें 2009 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत विश्वास पैदा कर देती है जब राहुल की रणनीति में वह 23 सीटें जीती थीं।